हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 215 देहरादून, बृहस्पतिवार, 16 फरवरी, 2023 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

आयुक्त गढवाल सुशील कुमार ने प्रस्तावित जी-20 कार्यक्रम पर ली बड़ी बैठक 3

कैबिनेट के फैसले : पार्क, सड़क, दुकान स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित होंगे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 15 फ़रवरी , मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 52 निर्णय लिए गए। प्रदेश की अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है और हर विभाग की अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

-आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।

-रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं।-नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र।

-दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।

-मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।

-ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक।

-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।

-राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।-वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।

-Msme के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी।

-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज

बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।

-सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।

-आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।

-समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान।

-स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे। -अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी।

-देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।

-उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।

-रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा। -उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर 20 दिन में किसी वाहन का पंजीकरण नहीं होता है तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।-ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय।-हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। डीपीआर बनकर हो चुकी है तैयार।-राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।-उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सुक्ष्म उद्योग विभाग ने तैयार की कस्टमाइज पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर मिलेगा लाभ।-सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।-उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।-पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।-सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।

-वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे।

-परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई ।

-राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड acqua पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा।

-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा-Ujvnl का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा

-युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।

-राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी।-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।

-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी।

-हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे

-पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।-पर्यटन विभाग के माध्यम से Gmvn और kmvn का होगा विलय।

-कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।

-नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।

-शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा-देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट।

-जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।

-वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।-4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।

-नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उप तहसील बनेगी।

मुख्यमंत्री राहत कोष में उपनल ने 11 लाख की आर्थिक मदद दी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 फरवरी , प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए उपनल द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में रु 11 लाख की आर्थिक मदद चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट किया। गौरतलब है कि इससे पूर्व में भी प्रदेश में आयी दैविक आपदाओं से निपटने के लिए उपनल द्वारा समय-समय पर आर्थिक मदद दी गयी। इस अवसर पर उपनल के प्रबंध निदेशक चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, उप महाप्रबंधक (वित्त) कर्नल मनोज रावत उपस्थित रहे।

■ मंत्री गणेश जोशी ने 11 लाख का चेक मुख्यमंत्री को किया भेंट

पेट रहेगा दुरुस्त, अगर पिएंगे अमरुद की ठंडाई

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , अमरूद गुणों से भरपूर फल है और ये पेट की गर्मी खत्म करने में भी मदद करता है. व्रत के दौरान अगर पेट की गर्मी बढ़ जाए तो अमरूद की ठंडाई इसे दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकती है. महाशिवरात्रि के मौके पर कई तरह की ठंडाई प्रयोग की जाती है. शिवभक्तों को ठंडाई का प्रसाद भी बांटा जाता है. अमरूद की ठंडाई न सिर्फ स्वादिष्ट रहती है बल्कि सेहत के लिहाज से भी ये काफी फायदेमंद होती है. ऐसे में आप चाहें तो इस बार अमरूद की ठंडाई की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

अमरूद की ठंडाई जितनी टेस्टी होती है, इसे बनाना उतना ही आसान भी होता है. इसे बनाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं. अगर अब तक आपने कभी अमरूद की ठंडाई नहीं बनाई है तो हमारी बताई रेसिपी की मदद से आप बेहद आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं. आइए बताते हैं अमरूद ठंडाई बनाने की रेसिपी.

अमरूद ठंडाई बनाने के लिए सामग्री

दूध – 1 गिलासअमरूद जूस – 1/2 गिलासबादाम – 1/2 कपपिस्ता – 1/4 कपकाजू – 1/4 कपखरबूज बीज – 1 टेबलस्पून (वैकल्पिक)इलायची पाउडर – 2 टी स्पूनकाली मिर्च – 1 टी स्पूनसौंफ – 1 टी स्पूनफूड कलर – जरूरत के मुताबिक (वैकल्पिक)आइस क्यूब्स – 5-6

अमरूद ठंडाई बनाने की विधि

अमरूद की ठंडाई बनाने के लिए अमरूद से पहले जूस निकाल लें. इसके बाद एक कड़ाही को मीडियम आंच पर गर्म करें और इसमें बादाम डालकर भून लें. बादाम जब रोस्ट हो जाए तो उसे एक बाउल में निकालकर रख दें. इसी तरह काजू और पिस्ता को भी थोड़ा-थोड़ा भून लें. ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होने के बाद कड़ाही में सौंफ डालें और उसे भी हल्का सा भूनें और फिर निकाल लें. अब मिक्सर जार में काजू, बादाम, पिस्ता, सौंफ, खरबूज बीज और काली मिर्च को डालकर सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें.

समोसे पकौड़े का जायका आपके लिए बन सकता है. हार्ट अटैक कैंसर का खतरा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फरवरी , अधिक तले-भुने पदार्थ खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर के मुताबिक, खाद्य तेल को बार-बार गर्म करने से प्रोटीन, वसा जल जाता है और पौष्टिकता खत्म हो जाती है। इससे पाचन में दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पेट की समस्या से पीड़ित मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पर डॉक्टर ने विशेष सलाह दी है। अन्यथा कैंसर तक की समस्या पैदा हो सकती है। डॉक्टर के मुताबिक तेल को बार-बार गर्म करके बनाए जा रहे पकवानों को खाने से सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। इससे पेट में गैस, अपच, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर की समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर की मानें तो यह खाना किडनी की खराबी से लेकर कैंसर तक की बीमारी पैदा कर सकता है।

आजकल फास्ट फूड का आलम का यह है कि गर्म समोसे, पकौड़े का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दुकानों, ठेलों पर सुबह से लोगों की भीड़ लगी रहती है। इन्हें खरीदते समय लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देते कि ये उनकी सेहत पर किस कदर भारी पड़ सकते हैं। कई दुकानदार बार-बार एक ही तेल को गर्म करके पकवान बनाते हैं. ये एसिड, तेल को हर बार गर्म करने पर पांच से दस फीसदी बढ़ता जाता है। सीएमएस महिला विंग के डॉ. ने बताया कि बार-बार तेल गर्म करने से प्रोटीन, वसा जल जाता है और पौष्टिकता खत्म हो जाती है। इससे पाचन में दिक्कत होती है।

कहा कि तेल को पचाने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इससे कैंसर सेल विकसित हो जाते हैं। पाचन क्रिया प्रभावित होने से लिवर भी खराब हो जाता है।

हानिकारक पदार्थ किडनी में जमा हो जाते हैं। इससे किडनी फेल हो सकती है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में आने वाले 40 फीसदी मरीज तो पेट में गैस, अपच, कब्ज आदि समस्या लेकर आते हैं। इनमें ज्यादातर लोग वो होते हैं, जो लंबे समय से बाहर का तला-भुना खा रहे होते हैं। किसी भी खाद्य तेल को तीन बार से ज्यादा गर्म नहीं किया जाना चाहिए। वरना खाद्य तेल का टोटल पोलर कंपाउंड (टीपीसी) बढ़ जाता है। 25 फीसदी से अधिक टीपीसी हो जाने पर खाना खाने योग्य नहीं होता है। लगातार अभियान चलाकर दुकानदारों को इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है।

गांजा फूंकने की नौकरी ? सैलरी है 88 लाख

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , दुनिया में कहीं भी पहुंच जाइए, स्मोकिंग किसी न किसी रूप में लोगों को प्रभावित कर रही है. कहीं नेचुरल चीज़ों से लोग नशीला धुआं बना लेते हैं तो कहीं सिगरेट और बीड़ी से ही काम चला रहे हैं. स्मोकर्स की खास बात ये भी है कि वो इसे छोड़ने की बात तो रोज़ करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते. ऐसे ही गंजेड़ियों के लिए एक नौकरी मार्केट में आ चुकी है, यहां उन्हें गांजा फूंकने के बदले अच्छी-खासी सैलरी भी ऑफर की जा रही है.

कंपनी चाहती है एक्सपर्ट गंजेड़ी

कंपनी ने खासतौर पर गंजेड़ियों के गजब का जॉब ऑफर दिया है. नौकरी के विज्ञापन के मुताबिक, आपको सिर्फ गांजा फूंकना है और इसके बदले में 88 लाख रुपये भारी-भरकम सैलरी भी मिलने वाली है. अब गंजेड़ियों ने इस नौकरी के लिए लाइन लगा दी है यानि कम्पटीशन यहां भी कम नहीं है. सोशल मीडिया पर तो लोग इस नौकरी के बारे में सुनकर ही दंग हो रहे हैं लेकिन ये अजीबोगरीब जॉब ऑफर प्रोफेशनली गांजा पीने वालों के लिए निकाला गया है.

जर्मनी की एक कंपनी को एक ऐसे कर्मचारी की तलाश है, जो पेशेवर तरीके से गंजेड़ी हो. आप हैरान मत होइए, इस कंपनी का नाम ही Cannabis Sommelier है और उसे अपने लिए एक प्रोफेशनल स्मोकर की तलाश है. प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जांचने के लिए उन्हें 'वीड एक्सपर्ट' (Weed Expert) की तलाश है. कोलोन बेस्ड कैन मेडिकल, जर्मन फार्मेसी को दवा के तौर पर कैनबिस यानि भांग बेचती है. इसके लिए उसे ऐसे लोगों की तलाश है, जो उसके प्रोडक्ट को सूंघे, महसूस करे और स्मोक करके उसकी गुणवत्ता की जांच करे. इसके लिए 88 लाख रुपये सैलरी दी जा रही है मज़े की बात ये भी है कि इस नौकरी के लिए भी टफ कॉम्पिटिशन है क्योंकि गंजेड़ियों ने अर्ज़ियाँ की झड़ी लगा दी है.

इस वजह से 20% कपल अलग कमरे में सोते हैं, यह है बीमारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , पति-पत्नी और कपल्स का एक ही घर में रहकर भी अलग-अलग सोना सामान्य होता जा रहा है। रिसर्च के दौरान 20% जोड़े अलग बेडरूम में रात गुजारते हैं। 31% कपल्स ने बताया कि अलग सोने से उनके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है। 21% ने तो कहा कि इससे उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं। अब घरों को अलग सोने के हिसाब से डिजाइन कराने वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। इंटीरियर डिजाइनरों का कहना है कि कपल्स चाहते हैं कि दोनों कमरों की डेकोरेशन एक जैसी हो। ऐसे कपल्स अलग कमरे में सोने को अच्छा मानते हैं। वे अपनी नींद साथी के खर्राटों की आवाज में खराब नहीं करना चाहते हैं।

एक्सपर्ट्स बोले- साथ सोने से बेहतर होते हैं रिश्ते : कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एक साथ सोने से कपल्स के रिश्ते अच्छे होते हैं।

मनोवैज्ञानिक कहती हैं कि लोग प्रेम करने और जिंदगी साथ में गुजारने के लिए शादी करते हैं। इसलिए एक साथ सोने से संबंध गहरे होते हैं।हाउसवेयर्स एसोसिएशन के सर्वे में 46% लोगों का कहना है कि पार्टनर के जमकर खर्राटे लेने या बहुत अधिक करवट बदलने से तंग आकर उन्होंने अलग कमरे में रात गुजारने का निर्णय लिया है। अन्य कारण सोने का अलग समय या किसी काम में व्यस्त रहना भी है।20% लोगों ने कहा वे अपने लिए अलग जगह चाहते हैं इसलिए अलग सोते हैं। 22% लोगों ने बताया कि उन्होंने पिछले साल ही दूसरे कमरे में सोना शुरू किया है। इससे लगता है कि यह चलन अब बढ़ रहा है। वहीं, कुछ बुजुर्ग अपने परिवार के किसी कपल के अलग सोने को उचित नहीं मानते हैं।

आयुक्त गढवाल सुशील कुमार ने प्रस्तावित जी-20 कार्यक्रम पर ली बड़ी बैठक

देहरादून , 15 फरवरी , आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने मई-जून 2023 में प्रस्तावित जी-20 कार्यक्रम को लेकर अतिक्रमण विरोधी अभियान, स्थानीय व्यवस्था समिति की बैठक ली। बैठक में आयुक्त गढवाल मण्डल ने बैठक लेते हुए निर्धारित यात्रा रूट पर अतिक्रमण चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही चिन्हित वैकल्पिक रूट पर भी अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों यथा लोनिवि, दूरसंचार निगम, वन विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से अतिक्रमण चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें।

यूपीसीएल को सड़कों पर यातायात को बाधित करने वाले विद्युत पोल का चिन्हिकरण कर शिफ्ट करने तथा इन्टरनेट एवं केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक करते हुए केबलों को शिफ्ट करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित करने को कहा। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों में आपसी समन्वय हेतु समन्वय बैठक आयोजित करते हुए अपने-अपने विभागों से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही/व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने वाहनों की व्यवस्था, साज-सज्जा, स्ट्रीट लाईटें आदि कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को पैदल मार्ग को ठीक करने, पार्किंग, हैलीपैड आदि व्यवस्था बनाने के लिए आंगणन की कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करने को कहा।

बैठक में डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दलीप सिंह कुंवर, अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल नरेन्द्र सिंह क्वीराल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा सहित यूपीसीएल, जल संस्थान के अधिकारी आयुक्त कैंप कार्यालय में उपस्थित रहे तथा वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी टिहरी सौरव गहवार, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चैहान,

पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे , मुख्य विकास अधिकारी टिहरी मनीष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी अर्पूवा पाण्डे, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश नंनद कुमार सहित संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।

दमकल वाहन , हाइड्रेण्ट सिस्टम वनाग्नि काल में रहे तत्पर : सोनिका , डीएम देहरादून

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 15 फरवरी , जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में वनाग्नि सुरक्षा के संबंध में जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2023 के वनाग्निकाल हेतु फायर प्लान का प्रस्तुतिकरण पॉवर प्वाइण्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से किया गया।

जिलाधिकारी ने वनाग्नि सत्र के दौरान सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त किए जाने तथा इसके लिए उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने आदि योजनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने मास्टर कण्ट्रोल रूम, क्रू स्टेशनों, वायरलैस सिस्टम तथा उपयुक्त वाहनों को क्रियाशील किए जाने तथा वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ को राशन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए।

अग्निशमन विभाग को भी दमकल वाहन तथा हाइड्रेण्ट सिस्टम को वनाग्नि काल में तत्पर रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय हेतु संचार व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जन

जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से अपील किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून नितिशमणी त्रिपाठी, कैंप कार्यालय में उपस्थित रहे तथा अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।

चारधाम यात्रा के लिए बनाए यातायात प्लान : एसएसपी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी, 15 फरवरी मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी ने चारधाम यात्रा में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए अभी से रूट डायवर्जन, यातायात प्लान तैयार करने, पार्किंग स्थल चिह्नित कर बाजार के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। कहा कि पुलिस अधिकारी अभी से चारधाम यात्रा के रूट की सडक़ों की स्थिति का जायजा लेकर जहां-जहां सडक़ें सही करनी है, मुख्य स्थानों पर पानी की व्यवस्था आदि के लिए संबंधित विभाग से समंवय स्थापित कर उनको समय से पूरा कर लिया जाए। कहा कि यात्रा रूट में पडने वाले चैक पोस्ट, बैरियर जो कि जीर्ण-शीर्ण एवं खराब स्थिति में है उनकी मरम्मत कर ली जाए। पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में एसएसपी श्वेता चौबे ने आगामी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जिले के नीलकण्ठ महादेव मन्दिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सघन चेकिंग करने, संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करने, जिले में आवागमन करने वाले वाहनों, व्यक्तियों की लगातार चेकिंग करें। एसएसपी ने सभी सीओ व थानाप्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शांति, कानून व्यवस्था को देखते हुए अभी से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने गैंगस्टर ऐक्ट के तहत व नशे के अवैध धंधों में लिप्त, अवैध रूप से संपति अर्जित करने वालो के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी ने सोशल मीडिया और मॉनिटरिंग सैल को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कंट्रोल बर्निंग से जंगलों की सुरक्षा में जुटा वन महकमा

पौड़ी। फायर सीजन शुरू होते ही वन महकमा अपनी तैयारियों में जुट गया है। वनाग्नि डेंस फॉरेस्ट तक न पहुंचे इसके लिए इन दिनों पौड़ी डिविजन की छह रेंजों में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। वहीं वन विभाग की मानें तो अभी तक 10 हेक्टेयर क्षेत्र में कंट्रोल बर्निंग की जा चुकी है। फायर सीजन का बुधवार से आगाज हो गया है। जिसको लेकर वन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। वन विभाग इन दिनों डेंस फोरेस्ट को वनाग्नि से बचाने के लिए कंट्रोल बर्निंग कर रहा है। जिससे कि आबादी वाले क्षेत्रों से जंगलों को पहुंचने वाली आग से बचाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी स्वपनिल अनिरूद्ध ने बताया कि 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में वनाग्नि से बचने के लिए सबसे पहले कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। बताया कि इन दिनों पौड़ी डिविजन की पौड़ी, पैठाणी, पश्चिमी अमेली समेत सभी छह रेंजों में कंट्रोल बर्निंग की जा चुक है।

मुख्यमंत्री ने किया बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के भवन का शिलान्यास

देहरादून, 15 फरवरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में गौलापार हल्द्वानी में बनने जा रहे बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता होने के नाते प्रदेश के लगभग 25 हजार अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के लिये गौलापार हल्द्वानी में बार कांउसिल ऑफ उत्तराखण्ड के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के चेयरमैन एवं सभी सदस्यों एवं प्रदेश के लगभग 25 हजार अधिवक्ताओं को उत्तराखण्ड में स्वयं के भवन निर्माण एवं भूमि क्रय करने एवं उस पर कार्यालय का निर्माण करने की बधाई देते हुए कहा कि कार्यालय के निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा समय पूर्ण हो तथा इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड प्रदेश के सभी 25 हजार अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काउंसिल के भवन का भविष्य की जरूरतों की दृष्टि से बेहतर ढंग से निर्माण किया जाय, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस भवन के बनने के बाद हाईकोर्ट व अन्य कार्यों से आने वाले अधिवक्ताओं के लिये काफी सुविधा हो जायेगी।

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के चेयरमैन मनमोहन लाम्बा द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लगभग 25 हजार अधिवक्ताओं की पत्रावलियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय में बैठने एवं कार्य करने की सुचारू व्यवस्था नहीं थी इसलिये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड ने अपने अधिवक्ताओं से धन एकत्रित कर गौलापार में कार्यालय के भवन निर्माण की भूमि दिनांक 24 अगस्त, 2022 को क्रय की है तथा बार काउंसिल का नाम उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया है। चैयरमैन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूरे देश में कुल 21 बार काउंसिल हैं और उत्तराखण्ड बार काउंसिल पूरे देश में पहली बार काउंसिल है जिसने अधिवक्ताओं से धन एकत्रित कर बार काउंसिल के कार्यालय के निर्माण हेतु अपनी अपनी भूमि क्रय की है।

इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के वाइस चेयरमैन राव मुनफैत अली, वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र पुण्डीर, चंद्र शेखर तिवारी, योगेन्द्र तोमर, सुखपाल सिंह, अनिल पंडित आदि उपस्थित थे।

रुद्रप्रयाग के एक युवक की लगी बंपर लॉटरी, ड्रीम 11 से रातों-रात बना करोड़पति

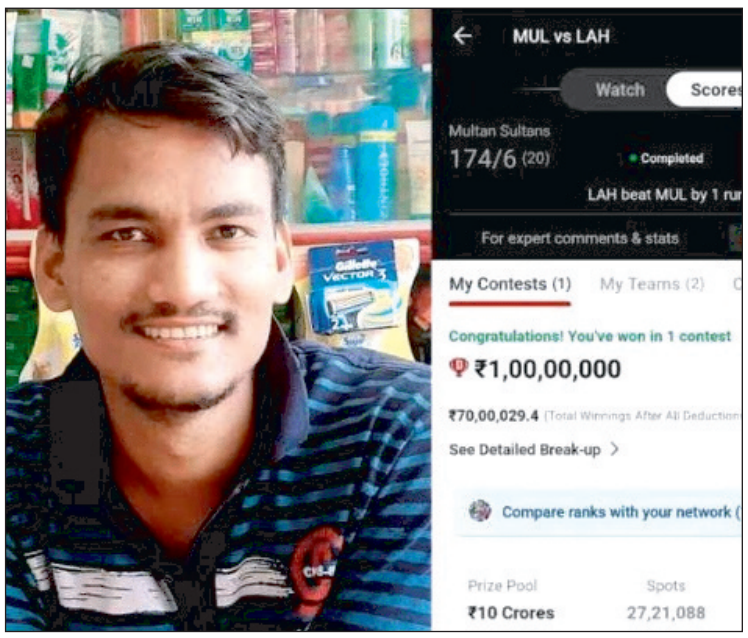

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयाग , 15 फ़रवरी : रुद्रप्रयाग के रहने वाले रविंद्र नेगी की किस्मत रातों-रात बदल गई और वो करोड़पति बन गए। जी हां रविन्द्र नेगी फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। रविन्द्र नेगी ने ड्रीम 11 पर टीम बनाकर एक करोड़ का इनाम जीता है। आपको यहां ये भी बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मुकाबला सोमवार की शाम लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के बीच खेला गया था। इस मुकाबले में लाहौर की टीम ने 175 रन बनाए जवाब में मुल्तान के सुल्तान टीम 174 रन ही बना सकी। उधर, लाहौर की एक रन से जीत हुई और इधर रुद्रप्रयाग के दुकानदार रविन्द्र नेगी की किस्मत खुल गई। रवींद्र नेगी ने दो टीमें लगाई थी, जिसमें से एक टीम ने लीग में पहला स्थान प्राप्त किया। इस तरह से वो करोड़पति बन गए। धनराशि जीतने के कुछ दिन बाद ही ड्रीम 11 द्वारा टैक्स काटकर खाते में इनाम की रकम भेज दी जाती है। खैर, रवींद्र की इस लॉटरी से उनके दोस्त परिवार रिश्तेदार बहुत ही खुश हैं।

देहरादून के अस्पताल में प्रीती अमिताभ की मोहब्बत बनी मिसाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 15 फ़रवरी , करनी है रब से एक गुजारिश, तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी न मिले , हर जन्म में साथी हो तुम जैसा, या फिर कभी जिन्दगी ही न मिले। यह पंक्तियां कोटद्वार निवासी प्रीति ने अपने पति अमिताभ को वेलेंटाइन डे पर किडनी देकर चरितार्थ कर दी। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के यूरोलॉजी व नैफ्रोलाजी की टीम ने मिलकर वेलेंटाइन डे पर मरीज का सफल किडनी प्रत्यारोपण किया। आयुष्मयान योजना के अन्तर्गत मरीज़ का किडनी प्रत्यारोपण किया गया।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में आयुष्मयान योजना के अन्तर्गत पहले भी किडनी प्रत्यारोपण हो चुका है। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि कोटद्वार के रहने वाले अमिताभ राणा को लंबे समय से गुर्दा रोग समस्या थी, वह श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के वरिष्ठ नैफ्रोलोजिस्ट डॉ आलोक कुमार की देखरेख में पिछले 7 माह से डायलिसिस पर थे। पत्नी प्रीति राणा ने आगे आकर मोहब्बत की बेमिसाल नज़ीर पेश की। आज के समाज में जहां घरेलू हिंसा, तलाक व पति पत्नी में आपसी समझ व सूझबूझ की कमी के ढेरों मामले प्रकाश में आते हैं। ऐसे में यह मामला समाज के लिए एक नज़ीर है।

प्रीति ने वेलेंटाइन डे के दिन पत्नी अमिताभ को किडनी देकर समाज में प्रेम, त्याग, समर्पण व वैवाहिक रिश्ते को निभाने की उत्कृष्ट मिसाल पेश की। किडनी प्रत्यारोपण टीम में डॉ विवेक विजन, डॉ कमल शर्मा, डॉ विमल कुमार दीक्षित, डॉ आलोक कुमार, डॉ विवेक रोहिला, डॉ आशुतोष, डॉ अपूर्व, किडनी प्रत्यारोपण की समन्वयक सुषमा कोठियाल, अमितव, विजय का विशेष सहयोग रहा। और इस तरह से महंत इंद्रेश के लिए भी खास हो गया वेलेंटाइन डे का दिन।

IPS नवनीत सिकेरा ने शेयर की देसी जुगाड़ की गज़ब तस्वीर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , जुगाड़ कमाल की कला है जिसमें भारतीय उस्ताद हैं! जी हां, मसला कोई भी हो... भारतीय हल निकाल ही लेते हैं। अब इन चचा को ही देख लीजिए, जिन्होंने ट्रेन की भीड़ में भी बैठे-बैठे सोने का मस्त जुगाड़ निकाल लिया। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के एडीजी ने ट्विटर पर शेयर की, जिसके बाद मामला इंटरनेट पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया की पब्लिक चचा के जुगाड़ की फैन हो गई है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर फंदा सिर से गर्दन में आ गया ना, तो चचा ठीक से ही सो जाएंगे!

अद्भुत जुगाड़ की यह धांसू तस्वीर ट्विटर यूजर @navsekera ने बुधवार को शेयर की। उन्होंने 'अतुल्य भारत' हैशटैग के साथ मजाकिया लहजे में लिखा- इस जुगाड़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। खबर लिखे जान तक उनके ट्वीट को 37 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से अधिक रीट्वीट्स मिल चुके हैं। साथ ही, सैकड़ों यूजर्स ने इस पर अपनी मन की बात भी लिखी है। कुछ लोग तो बंदे को इस हैरतअंगेज जुगाड़ के लिए दंडवत प्रणाम भी करने को तैयार हैं!

इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुछ यात्री भारतीय रेल में सफर कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स बड़े ही अलहदा अंदाज में सोता दिख रहा है। दरअसल, बंदे ने देसी जुगाड़ से अपने सिर को नीचे गिरने से रोका हुआ है। मतलब, वो होता है ना कि जब हम बैठे-बैठे सोने लगते हैं तो हमारी गर्दन एक तरफ गिरने लगती है। इसके कारण कभी-कभार जोर का झटका लगता है और आदमी नींद से जाग जाता है। अब भीड़ में किसी का सहारा भी तो नहीं ले सकते। ऐसे में इस बंदे ने एक गमछे की मदद से ऐसा कारनामा किया कि इंटरनेट की पब्लिक उसके जुगाड़ की दीवानी हो गई।

हरिद्वार पुलिस ने लेखपाल / पटवारी पेपर प्रकरण में 2 और गिरफ्तारी की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

- मुख्य आरोपियों के 'मौसेरे भाई एवम छात्र' की गिरफ्तारी के साथ ही संख्या पहुंची - 15
- रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने और उनकी निगरानी का मिला था जिम्मा

हरिद्वार , 15 फ़रवरी , एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पटवारी/लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा में धांधली के सम्बन्ध दर्ज मुकदमे में एसआईटी के हाथ एक और सफलता हाथ लगी।

एसआईटी द्वारा अभी तक 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी ने विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त देवी सिंह एवम धर्मेंद्र को हरिद्वार से दबोचा गया। अभियुक्त देवी सिंह उक्त प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे का *मौसेरा भाई* है एवम अभियुक्त धर्मेंद्र मुख्य अभियुक्त राजपाल का छात्र रहा है जिसके द्वारा मोटी रकम के लालच में बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा का पेपर पढ़वाने और उनकी निगरानी करने के लिए 25=25 हजार रुपए एडवांस लिए गए थे, जो इनके द्वारा खर्च करना बताया गया। रिजॉर्ट में आए अभियर्थियों को चिन्हित कर उनसे आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे है।

VETO Power : क्या आप जानते हैं वीटो पावर क्या हैं ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , वीटो एक लैटिन शब्द हैं जिसका अर्थ हैं – "मैं निषेध करता हूँ". संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य देशो को मिला हुआ विशेषाधिकार ही "VETO Power (वीटो पॉवर)" कहलाता हैं. जिन देशों के पास यह विशेषाधिकार होता हैं वो परिषद् में प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या उसे नकार सकते हैं. भले ही उसके पक्ष में कितने भी वोट पड़े हों. किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए परिषद् के सारे स्थायी सदस्यों का वोट और 4 अस्थाई सदस्यों का वोट मिलना जरूरी होता हैं. सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य जिन्हें "Veto Power" प्राप्त हैं वे देश इस प्रकार हैं –

Veto Power Countries – अमेरिका (America), रूस (Russia), ब्रिटेन (United Kingdom – UK), फ्रांस (France) और चीन (China).

वीटो पॉवर कैसे मिलता हैं ?

वीटो पॉवर उन देशों को नही मिलता हैं जो माँगते हैं, यह उन देशों को मिलता हैं जो इसके क़ाबिल हैं. भारत या कोई अन्य देश तभी वीटो पॉवर पा सकता हैं जब सुरक्षा परिषद् के सारे स्थाई सदस्यों का सकारात्मक मतदान प्राप्त हो और अस्थाई सदस्यों का दो-तिहाई (2/3) सकारात्मक मतदान प्राप्त हो.दुसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की औद्योगिक, राजनितिक, आर्थिक और सैन्य वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट यानि वीटो पॉवर देने की पेशकश की गई लेकिन नेहरू जी ने चीन के लोगों के गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पॉवर लेंते से इनकार कर दिया.

वीटो पॉवर से सम्बन्धित अन्य तथ्य

संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना सुरक्षा परिषद् की मुख्य ज़िम्मेदारी हैं. इस कारणवश एक मुहावरे के रूप में इस "दुनिया का पुलिसमैन" भी कहा गया हैं.

यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग हैं और एक प्रकार से कार्यपालिका हैं.

सुरक्षा परिषद् में कुछ 15 सदस्य होते हैं जिनमे 5 स्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं.

सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता हैं. प्रक्रिया सम्बन्धी मामलो में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता हैं, जिनमें पाँचों स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता हैं.पाँचों स्थायी सदस्य देशों की सहमति महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो (निषेधाधिकार) शक्ति के रूप में जाना जाता हैं. यदि कोई स्थायी सदी किसी निर्णय से सहमत नही हैं, तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता हैं. इस दशा में 15 में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं.यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नही करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता हैं तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता हैं.

अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ई. में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था.चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ई. में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था.चीन ने वीटो पॉवर का उपयोग लगभग 12 बार किया हैं जिसमें 4-5 बार भारत के विरोध में किया हैं.

भारत को अब तक वीटो पॉवर क्यों नही मिला ?

भारत पिछले कई सालो से सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता यानि वीटो पॉवर के लिए प्रयास कर रहा हैं लेकिन अब तक सफ़लता नही मिली हैं. इसके ये कुछ मुख्य कारण हैं.सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य (जिनके पास वीटो पॉवर हैं) अपनी शक्ति को किसी अन्य देश के साथ साझा नही करना चाहते हैं इसलिए भारत को वीटो पॉवर मिलने में दिक्कत हैं.चीन नही चाहता कि भारत को वीटो पॉवर मिले.भारत सुरक्षा परिषद् में एक नही चार सीटों की मांग करता हैं, भारत यह मांग जी-4 सदस्य देशों (जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील) के लिए करता हैं. इसकी वजह से भी भारत को वीटो मिलने में देरी हो रही हैं.

चूल्हे की राख 1800 रु. किलो बेच रही कम्पनी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , आपको याद न हो तो बुजुर्गों से पूछ लीजिये कि गाँव देहात में जिस राख से बर्तन मांजा जाता रहा है उसकी क्या कीमत होती थी जवाब मिलेगा फ्री ... आज भी आपको ये सफाई का पाउडर देश के गाँव में मुफ्त मिल जायेगा लेकिन क्या यकीन करेंगे कि Ash Powder के नाम से बिकने वाली ये राख ऑनलाइन बाजार में 1800 रुपये प्रति किलो है. Cow Dung के नाम से उपले को पैकिंग कर बेचा जा रहा है. इसके लिए 450 रुपये कीमत रखी गई है. Chew Sticks मतलब दातून, इसे ऑनलाइन 100-150 रुपये में बेचा जा रहा है.

इंटरनेट के दौर में हम सभी तरह की चीज़ों को घर से ही ऑर्डर कर देते हैं. नए जमाने में हमने पुराने तरीकों को बदला है. अब हम सिर्फ सामान ही ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं बल्कि हमने अपनी जीवनशैली बदल दी है. जीवनशैली बदलने के कारण हमारे शरीर पर इसका बुरा असर भी पड़ा है. पहले हम लस्सी पीते थे, सत्तु का शर्बत पीते थे, मगर आजकल हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं. पहले घर में चना-चबेना खाते थे, मगर आज हम चिप्स खा रहे हैं. याद होगा बचपन में हम दोने में खाना खाते थे, मगर आज प्लास्टिक की प्लेट में खाना खा रहे हैं.

बर्तन धोने के लिए हमारे पूर्वज राख का इस्तेमाल करते थे. मगर आजकल हम बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं ऑनलाइन कंपनियां फिर से लोगों को वही चीज़ें महंगे दामों में बेच रही है.फ्री में मिलने वाली चूल्हे की राख अमेजन पर 1800 रुपये प्रति किलो मिल रही है. आप इस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं. इस तरह अमेजन पर कई ऐसी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, जो हमें बिल्कुल मुफ्त में मिला करती थी. उपले हो या दातून, खाट हो या फिर पूजा के लिए लकड़ी... सबकुछ ऑनलाइन मिल रहा है. इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.

कर्णप्रयाग के प्रभावितों ने मांगे प्री फेब्रिकेटेड घर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चमोली। नगर के बहुगुणानगर सहित अन्य जगह हो रहे भूधंसाव के लिए प्रशासन और विधायक अनिल नौटियाल ने प्रभावितों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रभावितों ने मांग की कि जब तक भूधंसाव का स्थायी हल नहीं निकलता तब तक सरकार उनके लिए भी जोशीमठ की तर्ज पर प्री फेब्रिकेटेड घर बनाए। जिससे प्रभावित पुनर्वास तक सुरक्षित ढंग से रह सके। मंडी समिति परिसर में आयोजित बैठक में बहुगुणानगर के आपदा प्रभावित पंकज डिमरी, सभासद हरेंद्र बिष्ट, बीपी सती, पुरुषोत्तम कोठियाल, पुष्कर रावत, कमला रतूड़ी सहित अन्य ने कहा कि बहुगुणानगर में करीब 38 घर भूधंसाव की जद में है। करीब दस माह से चल रही समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि कई बार यहां सर्वे कर दिया गया है। ऐसे में स्थायी समाधान तक आपदा प्रभावितों के लिए प्री फेब्रिकेटेड घर बनाएं जाएं।

ईड़ाबधाणी के उमेद सिंह ने गांव में भूधंसाव की समस्या बताई और बताया कि गांव का नंदा देवी मंदिर में भूधंसाव की जद में है। अनिल खंडूड़ी, संपूर्णानंद डिमरी, राजेश जोशी ने अपर बाजार भूधंसाव का ट्रीटमेंट करने की मांग की। सुधीर नेगी, सुभाष नौटियाल ने सुभाषनगर में हो रहे भूधंसाव से खतरे को बताया। वहीं लक्ष्मी जोशी, वरूण मिश्रा ने शक्तिनगर में जल निकासी और रास्तों की समस्या को प्रमुखता से रखा। मुकेश डिमरी ने एनएच पर सौतेला व्यवहार कर उसके मकान को क्षति पहुंचाने की शिकायत की। विधायक अनिल नौटियाल ने प्रभावितों की शिकायतों को ध्यान से सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया।

> कर्णप्रयाग के पूरे भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र के सर्वे के लिए कमेटी बना दी गई है। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के लिए सिंचाई विभाग काम कर रहा है। सरकार कर्णप्रयाग का पूरा ट्रीटमेंट करेगी।
> **-अनिल नौटियाल, विधायक**

इस दौरान लोगों ने जल निकासी के लिए बंद स्क्रबरों को खोलने की मांग की। बैठक में एसडीएम हिमांशु कफल्डिया, तहसीलदार सुरेंद्र देव, सिंचाई के ईई राजकुमार चौधरी, एई मोहन बुटोला, लोनिवि गौचर के ईई दिनेश बिजल्वाण, कर्णप्रयाग के जेई गौतम रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, नपा अध्यक्ष दमयंती रतूड़ी, नगर अध्यक्ष सुभाष चमोली, बृजेश बिष्ट, देवेंद्र नेगी, हरेंद्र टाईगर आदि मौजूद थे।

छात्रों ने गोलू देवता मंदिर का भ्रमण किया

चमोली। राइंका आगरचट्टी के 48 छात्र-छात्राओं के दल ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अतर्गत अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता मंदिर एवं कटार मल स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर का भ्रमण और दर्शन कर क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को गोलू देवता के महात्यम एवं प्राचीन सूर्य मंदिर, कटारमल के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारियां विद्यालय अध्यापिका किरन चौधरी, राजेश्वरी मिंगवाल व एनएस नेगी ने दी। प्रभारी डीएस कंडवाल ने बताया कि भ्रमण से बच्चों के ज्ञान वर्धन एवं सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा और छमता विकसित होती है ।

पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित गैलरी में दिखेगी यादों की झलक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित आगामी गैलरी को मार्च के अंत में जनता के लिए खोला जाएगा। गैलरी का एक हिस्सा पीएम मोदी के उनकी मां हीराबेन के साथ संबंधों को भी समर्पित होगा। राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक गैलरी जोड़ी गई है। बहुत जल्द इसको आम लोगों के लिए खोला जाएगा। माना जा रहा है कि अगले महीने यानी मार्च के अंत खुल जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए नोडल एजेंसी, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है।

इस गैलरी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बचपन के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों का भी प्रदर्शित देखने को मिलेगा। गैलरी का एक हिस्सा पीएम नरेंद्र मोदी के उनकी मां हीराबेन मोदी के साथ संबंधों

और उनकी शिक्षाओं को भी समर्पित होगा। गैलरी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रधान मंत्री का ध्यान, उनका आधुनिक स्वभाव और गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए उनके प्रयासों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

मोदी गैलरी में नीतिगत निर्णयों और कई परियोजनाओं का होगा दीदार

प्रधानमंत्री म्यूजियम गैलरी के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णयों और कई पालतू परियोजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि उज्ज्वला योजना के बारे में पीएम मोदी की दृष्टि और हजारों ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की

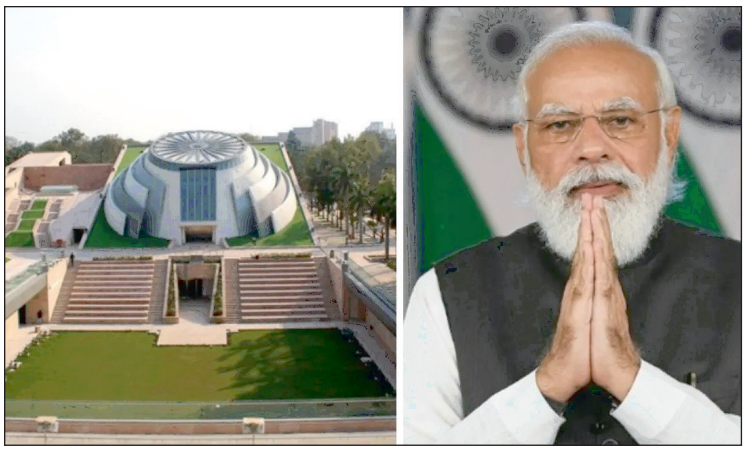

पेशकश उनकी मां को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देखने के उनके अनुभव से आई थी। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ उचित बिजली आपूर्ति से संबंधित उनके बचपन के अनुभव को दर्शाया जाएगा।

मां हीराबेन के लिए होगा विशेष सेक्शन

बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ गैलरी में मां हीराबेन के लिए विशेष हिस्सा समर्पित होगा। इसके में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के साथ संबंधों को प्रदर्षित किया जाएगा। गैलरी में दिखाया जाएगा कि मां की शिक्षाओं ने कैसे पीएम मोदी के जीवन को निर्देशित किया। बता दें कि बीते दिसंबर को उनकी मां का निधन हो गया था।

क्या आप जानते हैं फोन चार्जर में छोटी वायर क्यों देती हैं कंपनियां ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फरवरी , चार्जर किसी भी फोन के लिए बेहद जरूरी है. बिना इसके फोन चार्ज नहीं किया जा सकता है. लगभग हर फोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाता है, लेकिन इन चार्जर में मिलने वाली वायर काफी छोटी होती है. इस कारण आप कई बार फोन को चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. भले ही छोटे वायर से आपको परेशानी हो, लेकिन ये आपके लिए काफी फायदेमंद हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगा कि मोबाइल कंपनियां जानबूझकर आपके चार्जर में छोटा वायर देती हैं.अब आप सोच रहे होंगे आखिर मोबाइल चार्जर का केबल छोटे होने से आपको क्या फायदा है और कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? तो आज हम आपको इन सवालों का जवाब देने जा रहे हैं. दरअसल, मोबाइल कंपनियां फोन के चार्जर का वायर इसलिए छोटा देती हैं, ताकि आप अपने फोन को चार्जिंग में लगा कर ज्यादा समय तक यूज न कर पाएं.बता दें कि चार्जिंग में लगाकर फोन इस्तेमाल करने से उसकी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है. इतना ही नहीं मोबाइल चार्जिंग में लगाकर यूज करने से मोबाइल गर्म भी हो जाता है. इसके अलावा अगर आप फोन को चार्जिंग पर लगाकर यूज करते हैं, तो वह चार्ज होने में काफी ज्यादा वक्त लेता है. ऐसे में कई बार मोबाइल बैटरी ब्लास्ट कर सकती है. मोबाइल को चार्जिंग में लगा कर यूज करने से फोन का बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है.

पहले मिलता था लंबा वायर

कुछ साल पहले जब चार्जर का वायर काफी लंबा होता था, जिससे हम फोन को चार्ज में लगा कर कहीं भी अपने आसपास रख देते थे या फिर उसका इस्तेमाल करते रहते थे. हालांकि, समय के साथ लंबे वायर होने की खामियां सामने आने लगीं. फोन चार्ज पर लगाकर इस्तेमाल करने से फोन की बैटरी में दिक्कत आने लगीं और ग्राहक कंपनियों से बैटरी खराब होने की शिकायत करने लगे.

कंपनियों के पास आती थीं शिकायतें

लगातार बढ़ती शिकायतों से कंपनियों को भी नुकसान होने लगा. कंपनियों के प्रोडक्ट को लेकर गलत इंफोर्मेशन फैलने लगीं. यूजर्स अपने-अपने फोन की बुराइयां करने लगे. इसके अलावा कई बार बैटरी में ब्लास्ट होने की घटनाएं भी सामने आईं. इस समस्या से निपटने के लिए मोबाइल कंपनियों ने चार्जर के वायर को छोटा कर दिया, ताकि यूजर्स फोन चार्जिंग पर लगाकर उसे इस्तेमाल न कर सकें.

सर्वेक्षण : धरती उगलेगी इतिहास - खोदे जायेंगे 15 राज्य

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोज शुरू होने जा रही है. पुरातत्व विभाग के इस अभियान में देश के 15 राज्यों के 31 स्थानों पर उत्खनन (Excavation) होगा. इस दौरान पुराना किला, रखी गढ़ी समेत पांडव कालीन बागपत में व्यापक खोज होगी. इन उत्खनन में कई हजार साल पुरानी सभ्यता की खोज होगी. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन के लिए 15 राज्यों के 31 स्थानों की लिस्ट जारी की है.

भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता ही देश के इतिहास की झलक पेश करती है. शायद यही वजह है कि हमेशा जब भी आप इतिहास की झलक देखने, उसको निकलने का प्रयास करेंगे, तब ही आपको नई कहानी सामने देखने मिलेगी. पुरातत्व विभाग लगातार इस प्रयास में पिछले कुछ सालों से जुटा हुआ है कि देश की पौराणिक धरोहर सामने लाई जाए. इतिहास से देश की जनता को रूबरू कराया. चाहे वो सिनौली में 3500 से 4000 साल पुरानी

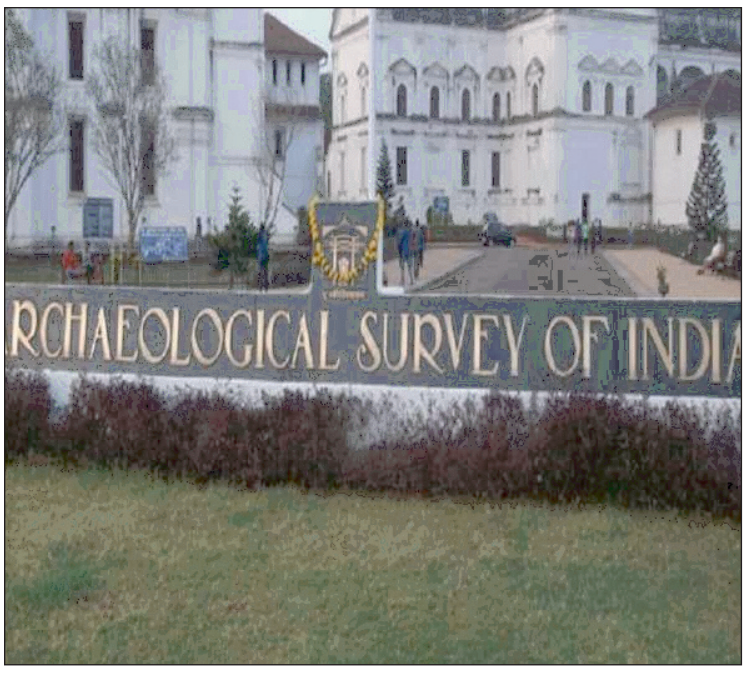

सभ्यता को सामने लाने का प्रयास हो या फिर रखी गड़ी में हजारों साल के अवशेष हो. ऐसे में अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश की 31 जगह पर नए इतिहास को सामने लाने का फैसला किया है. ये 31 स्थान देश के 15 राज्यों में चिन्हित किए गए हैं. इस नई खोज में पुरातत्व विभाग की कोशिश है कि अब तक सामने आ चुके अवशेषों के साथ नई सभ्यता को लोगों के साथ लाया जाए. इस नई खोज में बागपत की तिलवारा सकिन गांव हो कहा पर अब तक चांदी के सिक्के और मौर्य काल के सिक्के मिले है. इसके अलावा यहां पर कई मिट्टी के बर्तन भी खुदाई में सामने आए, जो मौर्य और शिंगू साम्राज्य के समय के बताए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली के पुराने किले को भी इस नई खोज का हिस्सा बनाया गया है. रखी गड़ी को लेकर केंद्र ने वहां के अवशेषों के लिए म्यूजियम पहले ही बना जा चुका है, अब यहां पर एक्सकेवेशन में जमीन के नीचे करीब 30 मीटर से जायदा के लक्ष्य को रख कर नई सभ्यता को सामने लाने का प्रयास किया जायेगा. इन 31 स्थानो की लिस्ट में 3 स्थान महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में 3 जगह और मध्य प्रदेश में 3 जगह को चिन्हित किया गया है. इस बार काफी समय से मध्य प्रदेश के मुरैना के बटेश्वर मंदिरों की खोज को भी इसमें शामिल किया गया है, जो काफी समय लंबित थी और करीब 1000 साल से जायदा के इतिहास की झलक अब तक देखने को मिली है.

ये है धामी सरकार की आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास नीति की पूरी जानकारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 15 फ़रवरी , जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा स्थायी विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति पर धामी मंत्रिमण्डल की बैठकमें अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस नीति के मुख्य बिन्दु क्या है आइये आपको बताते हैं।

(I) मुआवजे हेतु दरों का निर्धारण-

भूमि हेतु मुआवजे की दरः- तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आने के पश्चात भूमि के मुआवजे की दरों का निर्धारण किया जायेगा।

भवनों हेतु मुआवजे की दर -

(क) आवासीय भवनों हेतु दरें :- भवनों की लागत सी0पी0डब्ल्यू0डी० की प्लिंथ एरिया दरों में कोस्ट इंडेक्स लगाकर निकाली जायेगी। उक्तानुसार आने वाली भवन की लागत में से प्रभावित भवन के मूल्यह्रास (Depreciation) की धनराशि को घटाने के उपरान्त शेष धनराशि का मुआवजा दिया जायेगा।

(ख) दुकान तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के निर्मित भवन के मुआवजे के निर्धारण हेतु 5 क्षति स्लैब निर्धारित किये गये है। निर्धारित क्षति स्लैब के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

(II) आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास हेतु विकल्प-

(क) आपदा प्रभावित आवासीय भू-भवन स्वामी निम्न विकल्प 1, 2 अथवा 3 में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं-

विकल्प-1

निर्माण

आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का मुआवजा निर्धारित दर पर तथा भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।

विकल्प-2

आपदा प्रभावित व्यक्ति द्वारा भवन का मुआवजा प्राप्त करते हुये आवासीय भवन के हेतु अधिकतम क्षेत्रफल 75 वर्ग मी0 (50 मीटर भवन निर्माण हेतु तथा 25 मीटर गौशाला / अन्य कार्यों हेतु) तक की भूमि प्रदान की जा सकती है।

विकल्प-3

आपदा प्रभावित द्वारा अपनी भूमि एवं भवन के सापेक्ष निर्मित आवासीय भवन की मांग की जा सकती है। अधिकतम 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण कर दिया जायेगा तथा 25 मीटर भूमि गौशाला / अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी

(ख) दुकान / अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के लिये निम्नलिखित विकल्प संख्या-4, 5 एवं 6 मे से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं:-

विकल्प-4-

आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त व्यवसायिक भवन / दुकान का मुआवजा निर्धारित दर पर तथा भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर मुआवजा प्राप्त कर सकते है।

विकल्प-5

आपदा प्रभावित व्यक्ति द्वारा भवन का मुआवजा प्राप्त करते हुये दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान हेतु भूमि की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मी0 तक की भूमि प्रदान की जायेगी।

विकल्प-6

आपदा प्रभावित दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा निर्मित दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में चिन्हित स्थल पर अधिकतम 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) किराये पर रहने वाले परिवारों / व्यक्तियों के रोजगार के लिये व्यवस्था

यदि जोशीमठ में कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि एक वर्ष से अधिक समय से जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र में किराये पर दुकान लेकर कार्य कर रहा है एवं आपदा के कारण दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान की भूमि एवं भवन दोनों असुरक्षित होने के कारण उसका रोजगार प्रभावित हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक मुश्त रू0 2.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) Retrofitting क्षति हेतु व्यवस्था

तकनीकी संस्थानों द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षित भूमि पर स्थित भवनों की Retrofitting क्षति की तीव्रता के अनुसार सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

उक्त विकल्प संख्या 1 से 6 निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगें :-

1. यदि किसी प्रभावित परिवार के पास भूमि / भवन के स्वामित्व के वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो ऐसे परिवारों को सरकारी विभागों द्वारा प्रदत्त विभिन्न देयक बिलों यथा-विद्युत बिल, जलकर, सीवर कर भवन कर आदि के साथ ही शपथ-पत्र के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा। उक्त देयकों के बिल दिनांक 02 जनवरी, 2023 से पूर्व के होने आवश्यक है।2. भूमि की राहत राशि के भुगतान से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा भूमि से सम्बन्धित समस्त देयतायें पूर्ण कर दी गई हो। सम्बन्धित विभागों के द्वारा इस सम्बन्ध में No Dues Certificate देने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रभावितों को राहत राशि का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।3. प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि सर्वेक्षण टीम के द्वारा किये सर्वेक्षण एवं मापन के आधार पर राहत सहायता वितरित की जायेगी।4. पुनर्वास पैकेज / राहत सहायता के भुगतान से पूर्व प्रभावित परिवारों को पूर्व में वितरित पैकेज की अग्रिम धनराशि रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) / गृह अनुदान (यदि कोई हो) का समायोजन कर लिया जाए।5. प्रभावित हुए भूमि / भवन / दुकान के स्वामी द्वारा चाहे गये विकल्प के अनुसार मुआवजा दिये जाने का कार्य तथा भूमि / आवास / दुकान आवंटन का कार्य उप जिलाधिकारी जोशीमठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। 6. मुआवजे से असंतुष्ट प्रभावित व्यक्ति अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

संपादकीय

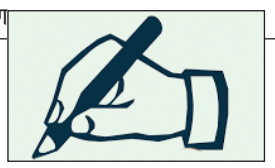

रक्षा क्षेत्र में प्रगति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया है कि 'एयरो इंडिया 2023' नये भारत की क्षमता, वास्तविकता और विकास का परिचायक है. रक्षा साजो-सामान, मुख्य रूप से लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर, हथियार आदि की इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, 98 देशों के प्रतिनिधिमंडल आये हैं तथा भारत समेत दुनियाभर के 800 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों के साथ हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह देश के प्रति विश्व के बढ़ते विश्वास को इंगित करता है. पहली बार इस प्रदर्शनी में इतनी बड़ी संख्या में निर्माता कंपनियां और संस्थान भाग ले रहे हैं. यह अवसर रक्षा क्षेत्र में भारत के विकास को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी है. इस क्षेत्र में हम तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उल्लेखनीय है कि हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय तक आयात पर निर्भर रहे हैं. जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, भारत अब केवल दुनिया की रक्षा कंपनियों के लिए बाजार भर नहीं रहा, बल्कि आज वह इस क्षेत्र का एक संभावित भागीदार है. अनिश्चितता के साथ बदलती विश्व व्यवस्था में रक्षा क्षेत्र में विकसित देश भी भरोसेमंद सहयोगी देश की तलाश में हैं. बीते वर्षों में वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ी है, देश में नीतिगत स्तर पर पारदर्शिता एवं स्थिरता आयी है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार हुआ है. इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और कंपनियों का आकर्षित होना स्वाभाविक है. भारत ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेक सुधार करते हुए निजी और विदेशी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता बनाया है. सरकार ने ऐसी कई रक्षा वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनका आयात नहीं किया जायेगा और उनकी खरीद घरेलू बाजार से ही की जायेगी. इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं. भारत का रक्षा निर्यात 2017 और 2021 के बीच 1,520 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,435 करोड़ रुपये हो गया तथा 2021-22 में निर्यात का यह आंकड़ा 14 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया. प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो देश में उत्पादन तो होगा ही, साथ ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध कराया जायेगा. ऐसा होने पर आयात पर निर्भरता में कमी आयेगी तथा उत्पादन खर्च में भी कमी आयेगी. रक्षा उत्पादों के मामले में तो इस पहल का सामरिक और रणनीतिक महत्व भी है.

दैनिक न्यूज़ वायरस
संपादक : मौ.सलीम सैफी, कार्यकारी संपादक : आशीष कुमार तिवारी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मौ.सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से प्रकाशित एवं न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून से मुद्रित। **फ़ोन :** 0135-4066790, 2672002 **RNI No. :** UT-THIN/2012/44094 **Cert. Ser. No. :** 31406 **E-mail :** dainiknewsvirus@gmail.com **Website :** www.newsvirusnetwork.com **YouTube :** TV News Virus
न्याय क्षेत्राधिकार : जनपद देहरादून (उत्तराखंड), भारत

डॉ निशंक की कहानी पर बनी फिल्म का सीएम धामी ने किया टीजर लांच

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 15 फरवरी , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में गढ़वाली फिल्म 'यु कनु रिस्ता' का टीजर लांच किया। यह फिल्म 17 फरवरी, देहरादून में रिलीज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की कि यह फिल्म उत्तराखण्ड के परिवेश, संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरों को सम्पूर्ण देश और विदेश में प्रचारित-प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुये पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल ने कहा कि डॉ. निशंक के उपन्यास 'छूट गया पड़ाव' पर बनी यह फिल्म एक शिक्षिका द्वारा अपनी एक असाध्य रोग से पीड़ित छात्रा के इलाज के लिये संघर्ष और सीमा पर शहीद हुये एक परिवार की कथा पर आधारित है, जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ-साथ उत्तराखण्ड की महान सैन्य परम्परा को दर्शाती हुई एक मार्मिक फिल्म है। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल, कार्यकारी निर्माता डॉ. बेचैन

कंडियाल, निर्देशक गणेश वीरान, अभिनेता राजेश मालगुड़ी, फिल्म कलाकार राजेश नौगांई, दिव्यांशी कुमोला, संजय चमोली, हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्ष आशना नेगी, फिल्म निर्देशक अशोक चौहान, निर्देशक महेश भट्ट, सुभाष भट्ट, बालकृष्ण चमोली एवं अजय बिष्ट सहित अनेक फिल्मी कलाकार उपस्थित थे।

ब्राह्मण देश हित में काम करता है और करता रहेगा : ब्राह्मण महासभा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फरवरी , देश के बडे राज्य और धार्मिक आस्था की धरती भुवनेश्वर (उड़ीसा) से ब्राह्मणों ने हुंकार भरी और समाज को एकजुट एवं एक मंच पर लाने में जुटी सर्व ब्राह्मण महासभा लगातार देश के कोने कोने में मौजूद बुद्धिजीवी, चिंतकों की बीच अपनी बात पहुंचा रही है। दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राजस्थान सहित 22 राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है, सर्व ब्राह्मण महासभा। ब्राह्मण सनातन काल से सबको साथ लेकर चलाता आया है। सभी जाति-धर्म-सम्प्रदाय को राह दिखाना और उनके सुख दुख में सहभागी के रूप में ब्राह्मण रहा है। ब्राह्मण जन्म, मरण, परण जैसे कर्मो में हर समाज के साथ रहता है और देश की आजादी के समय किये गये बलिदान को कोई भूल नही सकता है। ब्राह्मण समर्पण भाव से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभायेगा। ब्राह्मण देश हित में काम करता है और करता रहेगा

ये बात ग्लोबल ब्राह्मण फेडरेशन एवं सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने कही। समाज हित में 15 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।उड़ीसा के राष्ट्रीय समन्वयक संतोष मिश्रा ने कहा कि सर्व ब्राह्मण महासभा की जड़ों को देवभूमि में मजबूत करते हुए ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे है तथा पूरे उड़ीसा में सर्व ब्राह्मण महासभा को मजबूत और संगठित किया जाएगा। उड़ीसा के अध्यक्ष रवि नारायण महामात्र ने कहा कि ब्राह्मण पुरे विश्व का कल्याण के बारे में सोचता है और हमेशा विश्व कल्याण की ही बात करता है। वह कभी भी जातिगत बात नहीं करता है। राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ब्राह्मणों को सिर्फ सम्मान चाहिए। अगर ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया जाएगा तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र पाराशर, उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री आचार्य

नरेश शर्मा, उड़ीसा के राष्ट्रीय समन्वयक संतोष मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष रवि नारायण महापात्र, प्रदेश महामंत्री नारायण महापात्रा, पूर्णिमा दास, प्रफुल्ला महापात्र सहित सैकड़ों की संख्या में विप्रजन उपस्थित रहे।

प्रस्ताव, जो प्रमुख रूप से हैं-

1. ब्राह्मण देश हित में देश की अखंडता को बनाए रखने और पूरे विश्व में भारत देश का परचम लहराने के लिये सदैव तत्पर रहेगा।2. ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम जयंती पर पूरे देश में अवकाश की घोषणा करवाने हेतु देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि करोडो ब्राह्मणों के आराध्य देव की जयंती पर अवकाश की घोषणा कि जाये ।3. देषभर में गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाये, गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है और सनातन परम्परा में गाय का स्थान सर्वोपरि रहा है।4. देशभर में ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं का निर्माण और उच्च शिक्षा हेतु छात्र-छात्राओं को सहयोग के लिये पुरे देष में एक ठोस योजना बनाई जायेगी।5. ब्राह्मण समाज की अनुमानित जनसंख्या कितनी है उसका ब्यौरा इकट्ठा करने के लिये प्रत्येक जिले में आने वाले 3 माह में कमेटी का गठन किया जायेगा। 6. 1 लाख समाज की प्रतिभाओं को एक साथ एक ही दिन में सम्मानित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु प्रयास किया जायेगा।7. ज्योतिष, वास्तु, कर्मकाण्ड के निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जयंती समारोह में लगाये जायेगें।8. ब्राह्मण गुरुकुल की स्थापना की जायेगी साथ कौशल विकास जैसे कार्यक्रम भी हाथ में लिये जायेगें।9. प्रत्येक राज्य के प्रमुख आईएएस, आईपीएस, न्यायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, सांसद, विधायक, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी।10. छोटे कस्बों व गांवों में समाज के लोगों को संगठन से किस प्रकार जोडा जाये, किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये, उस पर विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी। साथ ही सामाजिक कुरूतियों को रोका जायेगा।11. सत्ता में पर्याप्त भागीदारी हो इसके लिये प्रत्येक परिवार में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा तथा वो मतदान अवश्य करें उसके लिये प्रेरित किया जायेगा।12. देशभर के मंदिरों, मठों और देवालयों पर सरकार की अनावश्यक दखल अंदाजी को बंद करवायेगें।13. प्रत्येक जिले में तहसील, गांव, ढाणी स्तर तक प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जयंती समारोह आयोजित करना।14. प्रत्येक जिले में मेधावी छात्रों का प्रतिभा सम्मान समारोह व शिक्षा हेतु सहायता कोष की स्थापना करना।15. राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण शिरोमणि, प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण रत्न, जिला स्तर पर ब्राह्मण गौरव इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से शादी विवाह में फिजूल खर्च को रोकने का प्रयास।

मिसाल : मिलिए 76 साल के स्टूडेंट से जिन्होंने 50 साल में पूरी की PhD !

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 फ़रवरी , कुछ करने की इच्छा हो तो उम्र कोई बाधा नहीं है। निक एक्सटेन इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। वह 76 साल के हो चुके हैं। 1970 में वह पीएचडी में एनरोल हुए थे। 50 साल बाद उन्होंने इसे पूरा किया है। 14 फरवरी को उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि से नवाजा गया। एक्सटेन को अपनी पत्नी क्लेयर और 11 साल की पोती फ्रेया के सामने यह सम्मान मिला। 1970 में एक्सटेन को पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में मैथमैटिकल सोशॉलजी से पीएचडी करने के लिए फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन, वह पीएचडी पूरी किए बिना 5 साल बाद ब्रिटेन लौट गए। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिसल ने उन्हें डॉक्ट्रेट की डिग्री से नवाजा है।एक्सटेन के नाम के आगे अब डॉक्टर लग चुका है। जब उन्हें डॉक्ट्रेट की डिग्री से नवाजा गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कई साल पहले उनकी यह चाहत पूरी हो गई होती। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। फिर भी उन्होंने इस ख्वाहिश को मन में जिंदा रखा। डॉ एक्सटेन ने ब्रिसल यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया। तब उनकी उम्र 69 साल थी। फिर उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में पीएचडी की। 75 साल की उम्र में पिछले साल यह पूरी हुई। 14 फरवरी को यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्हें उपाधि दी गई।

डॉ नकि एक्सटेन ने क्या कहा ?

ब्रिसल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर एक्सटेन का एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं जो जिंदगी का काफी समय ले लेती हैं। इन्हें समझना आसान नहीं होता है। काफी सोच-विचार की जरूरत पड़ती है। इसे समझने में मुझे 50 साल लग गए। एक्सटेन की रिसर्च की नींव में वो आइडिया हैं जो पांच दशक पहले अमेरिका में काम करते हुए उन्होंने महसूस किए। यह मानव व्यवहार को समझने के लिए नई थ्योरी है जो हर एक व्यक्ति रखता है। एक्सटेन कहते हैं कि इसमें बिहेवियर साइकॉलजी के नजरिये को बदलने की क्षमता है।

जीबी पंत संस्थान की कार्यशाला में शामिल हुए दून विवि के छात्र

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अल्मोड़ा। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा की ओर से मंगलवार को दून विवि के आग्रह पर उनके छात्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों ने छात्रों को तमाम जानकारियां दीं। पर्यावरण विज्ञान और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग दून विवि के एमटेक और एमएससी के छात्रों के लिए 'जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया गया। प्रतिभागियों को लैब से लेकर जमीन तक अनुसंधान और विकास का अनुभव देना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील नौटियाल ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें तमाम जानकारियां दीं। संस्थान के जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र के प्रमुख डॉ. आईडी भट्ट ने कार्यशाला के उदेश्यों की जानकारी दी। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की शोध और विकास गतिविधियों के बारे में भी बताया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जेसी कुनियाल ने 'एरोसोल एंड क्लाइमेट चेंज' आदि विषयों पर व्याख्यान दिए। प्रतिभागियों को संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं, सूर्यकुंज, ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र आदि का भ्रमण भी करवाया गया। दून विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विपिन कुमार सैनी ने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए संस्थान का आभार जताया। इस मौके पर डॉ. एके साहनी, डॉ. सतीष आर्य, डॉ. मिथिलेश सिंह, डॉ. केएस कनवाल, डॉ. सुमित रॉय, डॉ. कपिल केसरवानी, डॉ. आशीष पाण्डेय, डॉ. सुबोध ऐरी आदि मौजूद रहे।

डीएम ने किया मल्ला महल का निरीक्षण

अल्मोड़ा। डीएम वंदना ने बुधवार को मल्ला महल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दूसरे फेज के लिए प्रस्तावित कार्यों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि 20 मार्च तक हर हाल में दूसरे फेज के निर्माण कार्य शुरू हो जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पहले फेज के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। रानीमहल में बनाए जा रहे म्यूजियम में बिजली के कार्यों पर उन्होंने बेहद नाराजगी जताई। कहा कि कार्य बेहद सुस्ती से हो रहा है। चेताया कि यदि संबंधित ठेकेदार ने जल्द से जल्द कार्य पूरा नहीं किया तो ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सुस्त गति से हो रहे निर्माण कार्य पर उन्होंने बेहद नाराजगी जताते हुए ठेकेदार के प्रतिनिधि को खूब फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित ठेकेदार की रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को भेजें। ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।